MR. CHAIRMAN : This is the amendment before the House.

SHRI M. YUNUS SALEEM : I do not accept it.

SHRI DATTATRAYA KUNTE : Let it be put to vote.

MR. CHAIRMAN : I shall put the question to the House.

15.55 hrs.

[Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*]

MR. DEPUTY-SPEAKER : The lobbies have been cleared.

SHRI P. K. DEO (Kalahandi) : Will there be any more speeches ?

MR. DEPUTY-SPEARER : After the lobbies have been cleared, there is no more discussion.

SHRI M. YUNUS SALEEM : After having reconsidered the matter, I am inclined to accept the amendment.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Unless the House is unanimous, I have no option but to put it to the House.

SOME HON. MEMBERS : If he accepts the amendment, then it is all right.

SHRI M. YUNUS SALEEM : I have said that I accept the amendment.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Then, I think there is no object in putting it to the vote.

The question is :

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be referred to a Select Committee consisting of 16 members, namely :

(1) Shri C. K. Bhattacharyya
(2) Shri Kanwar Lal Gupta
(3) Shri Shiva Chandra Jha
(4) Shri K. M. Koushik
(5) Shri V. Krishnamoorthi
(6) Shri D. K. Kunte
(7) Shri P. Govinda Menon
(8) Shri Srinibas Misra
(9) Shri S. N. Misra
(10) Shrimati Sharda Mukerjee
(11) Shri K. Ananda Nambiar
(12) Shri A. S. Saigal
(13) Shri Ebrahim Sulaiman Sait
(14) Shri A. K. Sen
(15) Shri Tenneti Viswanatham
(16) Chaudhuri Randhir Singh

with instructions to report by the first day of the next session."

The motion was adopted.

15.59 hrs.

FOREIGN AID (MAINTENANCE OF ACCOUNTS) BILL

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपना विधेयक सदन के सामने विचार के लिये रखना चाहता हूँ। मैंने इस विधेयक में एक बात कही है कि जो विदेशी धन गलत तरीके से हमारे देश में आता है, उस के ऊपर कोई कड़ी निगरानी होनी चाहिये। मैंने यह कहा है कि कोई भी पार्टी, कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति अगर विदेशों से धन लेता है तो उस को सरकार को खबर करनी चाहिये। उस आदमी को या उस संस्था को यह चाहिये कि उस का पूरी तरह से हिसाब रक्खे, और एक साल हो जाने के बाद वह सारा हिसाब किताब सरकार को दे ताकि सरकार को यह मालूम हो कि कितना धन विदेशों से आया है, वह खर्च कैसे कैसे होता है और ठीक तरह से होता है या नहीं।

इस सदन में बार-बार बहस हो चुकी है। स्वयम गृह-मंत्री ने यह कहा था, जब उन्होंने रिपोर्ट रक्खी थी, कि वह एक विधेयक इस सम्बन्ध में सदन में रक्खेंगे। मुझे दुःख है कि आज ढाई साल बीतने के बाद भी ---यह रिपोर्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो की 1967 में सरकार को मिली थी--आज तक सरकार कोई विधेयक इस सम्बन्ध में नहीं लाई। आज अगर कोई हिन्दु-

[श्री कंवर लाल गुप्त]

स्तानी यह कहे कि मैंने यह पैसा अमरीका से लिया है, रूस से लिया है, चीन से लिया है या जापान से लिया है, तो उस के ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं चल सकता। आज हमारे देश में कोई कानून ऐसा नहीं है जो इस चीज पर प्रतिबन्ध लगता हो कि विदेशों से यहाँ पर धन लाया जाय अगर वह यहां पर लाया जा सकता हो।

16.00 hrs.

आज चार बड़े बड़े देश हैं जहाँ से हमारे देश में पैसा आता है। कुछ पैसा अमरीका से आता है, कुछ रूस से आता है, चीन से आता है और पाकिस्तान से आता है।

मोटे तौर पर चार बड़े बड़े देश हैं। और भी कुछ देश होंगे लेकिन इन चार से कितना धन आता है, उसका फैलाव कितना है, उसका असर कितना अधिक है अगर आप इसकी ओर ध्यान देंगे तो एक चिन्ताजनक स्थिति आपके सामने आ कर खड़ी हो जाएगी। वह स्थिति आज देश के सामने उपस्थित हो चुकी है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो कहा जा सकता है कि देश की सुरक्षा, प्रजातंत्र, सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। हमारी सरकार विदेशी सेनायें हमारे देश पर आक्रमण न करें, इसकी तो चिन्ता करती है लेकिन विदेशी धन की चिन्ता नहीं करती है। जिस मात्रा में विदेशी धन देश में आया है उसने एक चिन्ताजनक स्थिति पैदा कर दी है और हमारे देश की सिक्योरिटी और डिफेंस भी खतरे में पड़ रही है। मैं नहीं कह सकता हूँ कि प्रजातंत्र भी जीवित रह पाएगा या नहीं।

चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चारों तरफ विदेशी धन के जरिये बाहर के लोग हमारा गला घोंटने के लिए तैयार बैठे हैं। आप बड़े बड़े शहरों में जाएं आपको पता चलेगा कि पैसा दे कर लोगों को जासूस बनाया जा रहा है। आप सैंसेटिव एरियाज में जायें, असम में जायें, रांची में जायें जहां पर पिछड़े हुए लोग रहते हैं, काश्मीर में जायें, नागालैंड में जायें, मिज़ो लैंड में जायें, चारों तरफ पैसे के खेल की वजह से हमारे देश के साथ खिलवाड़ हो रही है, ऐसा आपको नजर आएगा।

इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटियों में आप जायें वहां भी यह खेल खेला जा रहा है। तीर्थ स्थानों में सन्यासियों के रूप में इस प्रकार के लोग काम करते हुए आपको मिल जायेंगे। गिरजाघरों में, मन्दिरों में भी विदेशों से पैसा ले कर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश हो रही है। इस सब का नतीजा यह हो रहा है कि हमारे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। यह समस्या किसी एक पार्टी की नहीं है, यह देश की समस्या है, राष्ट्र की समस्या है और सब को मिल कर इसको सुलझाना चाहिये। राजनीतिक क्षेत्र में इसके प्रभाव को आप देखें। स्वयं गृह मंत्री ने अपने बयान में कहा है कि चुनाव में पैसा आया है, चुनाव में जो लोग खड़े हुए थे उन में से कुछ ने पैसा लिया है। हमारा कहना यह है कि यह रुपया करोड़ों में आया है। मैं यह नहीं कहूँगा कि किस पार्टी ने लिया है। लेकिन जिस किसी पार्टी या व्यक्ति ने लिया है राजनीतिक कारणों से या अपना चुनाव लड़ने के लिए, वह देश द्रोही है और देश का शुभ चिन्तक नहीं है। लेकिन दुःख इस बात का है कि ढाई साल के बाद भी जो कदम सरकार को उठाने चाहिये थे उनको इसने नहीं उठाया है। चूंकि गृह मंत्री कोई विधेयक आज तक नहीं लाये हैं, इस वास्ते मुझे इस विधेयक को लाना पड़ा है।

हमने बार-बार कहा है कि कुछ अखबार हैं यहां जो विदेशों से पैसा ले कर विदेशों की नीतियों का गीत गाते हैं। इसको सी० बी० आई० की रिपोर्ट ने भी कनफर्म किया है। उसने कहा है कि पैट्रियाट और लिंक ने पिछले

सात साल में पचास लाख रुपया रूस से लिया । लेकिन सरकार ने अभी तक इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की है ।

यहां हमने एक सवाल पूछा था । केरल के डा० जार्ज थामस हैं । मैं नहीं जानता कि वह कौन सी कांग्रेस के लीडर हैं, इधर वाली कांग्रेस के या उधर वाली कांग्रेस के । गृह-मंत्री इसको ज्यादा जानते होंगे । गृह मंत्री महोदय ने अपने जवाब में हमें बताया था कि 1959 से ले कर 196 तक 16 लाख 39 हजार 472 रुपया विदेशों से उनके पास आया, उनके बैंक में जमा है । उन्होंने वह रुपया अपने अखबार में और अमरीका के प्रचार में खर्च किया, क्या यह ठीक बात है ?

आपको याद होगा कि यहां पर श्री निजलिंगप्पा ने भी चर्चा की थी कि राष्ट्रपति के चुनाव में विदेशों से पैसा आया, खर्च हुआ, लाखों रुपया खर्च किया गया । मन्त्री महोदय कह सकते हैं कि यह इरिसपांसिबल स्टेटमेंट है । लेकिन मैं इसको इरिसपांसिबल कैसे मानूं ? 22 साल तक आपके साथ मिल कर वह देश के भाग्य को चलाते रहे । आज जबकि वह आप से अलग हो गये हैं तो क्या वह इरिसपांसिबल हो गये हैं और आज तक रिसपांसिबल थे ? कल को आप भी इधर हट सकते हैं । सूचना यह है कि 11 अगस्त को, यानी इलैक्शन के पांच दिन पहले रूस की एम्बैसी ने रिजर्व बैंक से एक करोड़ रुपया निकलवाया और वह रुपया राष्ट्रपति के चुनाव में खर्च हुआ । मैं चाहता हूँ कि यह बात गलत हो । लेकिन यह इम्प्रेशन जनता का है कि देश के सब से बड़े पद के लिए इस प्रकार से विदेशी रुपया लगा है और उसका समर्थन श्री निजलिंगप्पा करते हैं । लेकिन उसके बाद भी सरकार चुप रहे, यह इम्प्रेशन अच्छा नहीं है । सरकार को इस इम्प्रेशन को दूर करना होगा । केवल यह कह देने से कि यह गलत है, दूर नहीं होगा । मैं चाहता हूं कि इसकी इनक्वायरी हो, इनवेस्टीगेशन होना चाहिये और लोगों को विश्वास दिलाया जाना चाहिये कि इस प्रकार से रूस का पैसा नहीं आया है ।

आंध्र का तम्बाकू का स्कैंडल भी है और वह भी आपके सामने है । उसका सम्बन्ध रूस से है । इस तरह से कालीकट के श्री नारायण है । उसका सम्बन्ध चीन से है । स्वयं गृह मंत्री ने इसी सदन में जवाब दिया था कि चीनी एम्बैसी से उनको चार बार पैसा मिला । केवल रूस की ही बात नहीं है । अमरीका की भी यही बात है । हिमालय की रिसर्च के सम्बन्ध में जो सी० आई० ए० का एजेंट था उसने अमरीका में जा कर कहा था कि मुझे सी० आई० ए० का एजेंट बनने का जो काम दिया जाता है वह बड़ा ही ट्रैचरस है । मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से बोर्डर एरियाज में लोगों को भेजना चाहे वे एक्सपर्ट हों या टैक्निशयनी, हों ठीक नहीं है । अमरीका से जो आपने वालैंटीयर्ज बुला रखे हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि उनकी कोई जरूरत है । क्यों नहीं सरकार उनको वापिस भेजती । जासूसों के देश के चारों तरफ बन जाएं, इसको किसी हालत में बरदाश्त नहीं किया जा सकता है । उनकी क्या जरूरत है ? मैं यह नहीं कहता कि सब क्रिस्चियन मिशनरीज खराब काम करते हैं । उन में से कई लोगों ने अच्छा काम किया है और कर रहे हैं । लेकिन आज से दस बरस पहले क्रिस्चियन मिशनरीज को बाहर से 10 करोड़ रुपया मिलता था, जब कि आज उन को लगभग 80 करोड़ रुपया मिलता है, जो कि सामान वगैरह मिला कर 100 करोड़ रुपया हो जाता है । उन में से कई लोगों की खासकर विदेशी मिशनरीज की गतिविधियां देश के हित में नहीं हैं । सरकार ने उन आठ क्रिस्चियन विदेशी मिशनरियों को देश से बाहर निकाल दिया, जिन की गतिविधियां एन्टी-नेशनल पाई गई । क्रिस्चियन मिशनरीज के पास जो पैसा आता है, उस का पूरा हिसाब-किताब होना चाहिए कि कितना पैसा आया और वह किस काम के लिए तथा कैसे खर्च हुआ ।

[श्री कंवर लाल गुप्त]

मैंने सुना है कि सरकार ने दूसरी सरकारों से इस आशय का एग्रीमेंट किया हुआ है कि कुछ संस्थाओं के लिए, जिनमें क्रिस्चियन मिशनरीज भी हैं, जो गिफ्ट या प्रेजेन्ट आयेंगे उन पर कोई ड्यूटी वगैरह नहीं लगेगी। इस बारे में भी कोई हिसाब या ब्यौरा सरकार के पास नहीं है। मैं चाहूंगा कि सरकार उन एग्रीमेंट्स के बारे में फिर से विचार करे। अगर मैं कोई चीज इंगलैंड से मंगवाता हूं, तो मुझे उसके लिए पांच हजार रुपये खर्च करने पड़ेंगे, जबकि क्रिस्चियन मिशनरीज और इस प्रकार की अन्य संस्थाओं को वह चीज केवल एक हजार रुपये की पड़ेगी। इस प्रकार सरकार का पैसा सरकार और देश के विरुद्ध खर्च किया जाता है। सरकार को इस बारे में कुछ कार्यवाही करनी चाहिए।

जहां तक शिक्षा के क्षेत्र का सवाल है, मुझे खुशी है कि सरकार ने एशिया फाउंडेशन को बन्द करने का आदेश दिया है और शायद अब वह बन्द हो गया है। लेकिन वह केवल एकही फाउंडेशन नहीं है, बल्कि हमारे देश में ऐसे दर्जनों फाउंडेशन आदि हैं, जिनको बाहर से पैसा मिलता है और वे उस पैसे के जरिये से उन लोगों में इनफिल्ट्रेट करते हैं और उनको प्रभावित करते हैं, जिनको बड़े-बड़े विद्वान कहा जाता है। इसके अलावा सरकार के कुछ बड़े बड़े अफसर हैं, जिनके दिमाग या तो रूस को बिके हुए हैं या अमरीका को। यह अवांछनीय प्रभाव खत्म होना चाहिए और उनका मैं जानता हूं कि इस सरकार के लोग इस शब्द से बहुत नाराज होते हैं—भारतीयकरण होना चाहिए। मेरा चार्ज है कि पिछले छः महीनों से सरकार उन एक्सपर्ट्‌स को बढ़ावा दे रही है, जिनका झुकाव एक विशेष देश की तरफ है। इस प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए। हमें ऐसे अफसरों को बढ़ावा देना चाहिए, जो भारत की दृष्टि से और भारत के हित में सोचते हैं। सरकार को इस तरह के फाउंडेशन्ज के बारे में एनक्वायरी करनी चाहिये कि उनके पास कहां से कितना पैसा आता है और वह पैसा किस तरह खर्च किया जाता है।

विदेशों से पैसा आने का माडस आपरेंडी यह है कि रूस और अमरीका आदि देशों के यहां पर ट्रेड के एजेन्ट हैं और उनके जरिये से यहां पैसा आता है। मेरी खबर है कि विदेशों से डिप्लोमेटिक बैग्ज में भी पैसा आता है। इसके अलावा कई प्रकार के प्रकाशनों को यहां भेजने की आड़ में भी पैसा आता है। मेरे पास किताबों की यह एक लिस्ट है। एक किताब है "साइनो-सोवियट रिलेशन्ज एंड आर्म्ज"। अमरीका में इस किताब की कीमत 72 रुपये है, जब कि वह यहां पर केवल 10 रुपये में बेची जाती है। इसी तरह से लेनिन के बारे में 464 पेजिज की एक किताब है, जिसकी छपाई की लागत ही बीस, पच्चीस रुपये होगी, लेकिन वह यहां पर बहुत सस्ते दामों पर बेची जाती है। इसी तरह की कई किताबें रशन एम्बैसी ने छापी हुई हैं। 144 सफहों की एक किताब "दि लेफ्ट विंग कम्युनिज्म," केवल चालीस पैसों में बेची जाती है और 798 पेजिज की एक किताब, "सिलेक्टिड वर्क्स," केवल चार रुपये में बेची जाती है।

मैंने सुना है कि हिन्दुस्तान में 33 पब्लिशिंग हाउस ऐसे हैं, जो रूस या अमरीका से सबसिडी ले कर उनका लिट्रेचर छापते हैं और लोगों के दिमागों में उन देशों के अनुकूल विचार भरते हैं। लेकिन हमें देखना होगा कि वे केवल अपना कमीशन ही लेते हैं या उनके बीच में कुछ और भी सौदा होता है। रूस की तरफ से कहा गया था कि ट्रैक्टर की एजेन्सियाँ किन्हीं विशेष आदमियों को दी जायेंगी मुझे खुशी है कि सरकार ने उस पर आपत्ति की लेकिन मैं आपको उन संस्थाओं और व्यक्तियों के नाम बता सकता हूं मुझे दिल्ली की उन संस्थाओं और व्यक्तियों के नाम मालूम हैं— जिनको सोवियत एम्बैसी कम्युनिज्म के प्रचार

के लिए अपने एजेन्ट्स के जरिये से पैसा दिलवाती है।...(व्यवधान)...माननीय सदस्य चुप रहें, वर्ना मैं नाम बता दूंगा। जो अखबार कम्युनिज्म का प्रचार करते हैं, उनमें उन एजेन्ट्स के एडवरटाइजमेंट्स छपते हैं। वे अखबार दूसरों से पचास रुपये इंच का लेते हैं और उनसे 500 रुपये इंच का। इस तरह से उन अखबारों को सबसिडाइज किया जाता है।

इसी तरह से कुछ प्रिंटिंग प्रेसिज में इन एम्बेंसीज का मैटीरियल छपता है। दो हजार का काम होता है और दो लाख रुपये दिखाये जाते हैं। कागज और छपाई भी दो लाख की देते हैं। जो पैसा प्रिंटिंग प्रेसिज को मिलता है, उसका बंटवारा होता है। इस बारे में भी एनक्वायरी की जानी चाहिए। मैं जानता हूं कि सरकार और मंत्री महोदय अभी तक और धन्धों में फंसे रहे हैं। मैं जानता हूं कि उनके सामने कितनी मुसीबतें हैं। उनकी एग्जिस्टेंस का सवाल है। लेकिन शायद डा० राम सुभग सिंह उनको गद्दी से न उतारें, लेकिन शायद निक्सन साहब या रूस के प्राइम मिनिस्टर या वहां के डिक्टेटर उतार दें। सरकार को उनकी तरफ से भी सतर्क रहना होगा।

क्या यह सही नहीं है कि कई देशों की सरकारों को विदेशी ताकतों ने उलट दिया? क्या यह सही नहीं है कि हमारे देश में भी विदेशी लोग रायट्स, दंगे-फसाद, करवाते हैं और उसके लिए पैसा देते हैं, लोगों को उकसाते हैं? क्या यह सही नहीं है कि नागालैंड और मिजो पहाड़ियों में जो आन्दोलन चल रहा है, उसमें विदेशियों का हाथ है? क्या यह सही नहीं है कि काश्मीर में जो जबर्दस्त आन्दोलन चल रहा है, उसमें पाकिस्तान का पैसा काम कर रहा है? क्या यह सही नहीं है कि शेख अब्दुल्ला जो कुछ कर रहे हैं, वह इसी पैसे से हो रहा है? लेकिन सरकार ने सिवाये एक रिपोर्ट पेश कर देने के कोई काम नहीं किया है। क्या इस प्रकार के गम्भीर राष्ट्रीय सवाल के बारे में सरकार इसी तरह सोती रहेगी? मैं गृह मंत्री महोदय पर क्रिमिनल नेग्लीजेंस का चार्ज लगाता हूं। सरकार ने चंडीगढ़ के सवाल को सुलझाया है और वह भी कई सवाल सुलझाना चाहती है। लेकिन उसको इस राष्ट्रीय सवाल को भी हल करना चाहिये, क्योंकि इसमें देश की सुरक्षा और देश के स्वाभिमान का प्रश्न है।

इस समस्या को सुलझाने के लिये कोई काम्प्रिहेंसिबल कानून बनाना शायद सरकार के के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि अंडर दि टेबल, अंडरहैंड मीन्ज से, इतना पैसा आता है कि उसके लिए कोई कानून बनाना मुश्किल होगा। लेकिन मैं सरकार से यह मांग करूंगा कि वह अपनी मशीनरी को मजबूत करे और इस काम के लिये एक अलग सैल बनाये। दिल्ली में एक रूसी इसी पिछले दस पंद्रह दिनों से गायब है, लेकिन अभी तक यह मालूम नहीं हो सका है कि वह कहां है। यह हमारी इंटेलिजेंस मशीनरी पर एक रिफलेक्शन है। जो विदेशी लोग यहां आते हैं, उनकी पूरी छानबीन होनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा है, इस काम के लिये एक अलग सैल बनाया जाये और अगर उस पर ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत हो, तो वह खर्च किया जाना चाहिए और इस प्रकार की कल्चरल, सोशल तथा एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्ज के बारे में पूरी जाँच करानी चाहिये।

आखीर में एक बात यह कहना चाहता हूं कि केवल कानून से मैं मानता हूं कि काम चलने वाला नहीं है। आपको लोगों को लोगों को एजूकेट करना पड़ेगा. मुझे दुख है कि कई ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया, जेलों में गये, अंग्रेजों की गोली का मुकाबिला किया, मैं जानता हूं उन को, ऐसे लोग आज तक बिक रहे हैं रूस और अमेरिका के हाथों में, इस तरह आज हमारे अन्दर चरित्र-हीनता आ गई है कि वह खुले आम कहते हैं कि हम लेते हैं पैसा। इसके लिये एक पब्लिक ओपिनियन ऐसी कारगर बनाने की जरूरत है सबसे मिलकर कि

[श्री कंवर लाल गुप्त]

कोई भी व्यक्ति अगर यह पता लग जाय कि पैसा लेता है विदेशों से तो उसको कंडेम करना चाहिए। सोसाइटी में उसको कोई स्थान नहीं होना चाहिए और सरकार उनको कोई किसी प्रकार का पद या इस प्रकार को चीज न दे जिससे उनका मान या सम्मान हो। इन शब्दों के साथ मैं आदरणीय गृह मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इस विधेयक पर विचार करके इसको समर्थन दें क्योंकि मैंने केवल यही कहा है कि जो भी बाहर से पैसा आता है उसका हिसाब रखा जाना चाहिये और किस चीज में खर्च हुआ यह सरकार को अगले साल बता देना चाहिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

> "That the Bill to provide for maintenance of accounts of the aid received by persons, organisations etc. from foreign Governments or foreign agencies, be taken into consideration."

SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI (Krishnagar): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am not opposed to the spirit of this Bill but I am surprised at what the hon. Member has just now said. It would appear from his speech that our Government is just sitting without taking note of the various things that he has said.

SHRI PILOO MODY (Godhra): He is not making notes.

SHRIMATI ILA PALCHOUDHURY: I am sure that Government does take note.

There must be some sort of a list so to speak to what the foreign agencies are doing all these years. I would just like to point out and bring to the notice of the hon. Minister that it is not only foreign money that comes to the country. I have given a calling-attention notice on this myself, I do not know if it will be admitted.

You know, Sir, that there has been a great deal of trouble in Calcutta recently. Arms and ammunitions have come into Calcutta in large quantities. It has been happening for over 10 years and the Government is aware of the challenge. Why is this not being looked into; why is nothing being done; how have students got ack-ack guns and AK47 guns to shoot with? All this ammunition has been coming and it has positively been proved that it is coming from China and Pakistan. How is it that for over 10 years it has been coming and nothing has been done? I hope the Government will take serious notice of the situation. The university in Calcutta has been closed down and the students have taken the law into their own hands. Everybody must have seen the cartoon that has come out in the papers today, where the Vice-Chancellor is asking the students not to "take law" and the students are surprised when he says that he asks them 'not to take the law into their own hands" and not, not to take up law as a subject of study.

Government should know the various subterfuges that are being practised and the channels that evidently are being sponsored by various parties who think that these channels are going to be the red line through which they are going to create chaos in India. Not only money has flown in, various literature has been supplied and arms and ammunitions have been supplied. That is why I say that I am one with the spirit of this Bill.

My hon. friend has said much about the missionaries. Many of them have done work that has not been very laudable but I must say at the same time that there have been a number of them who have done very good work in India and I would not smear with the tar brush all missionaries. But the Government must take note how the missionaries are spending their money; Sir, the cheap edition of very colourful books published by the Communist Party, sponsoring Russian and Chinese Communism, must be looked into.

SHRI P. P. ESTHOSE (Muvattupuzha): Are Communist books being published by missionaries?

SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI: What I am saying is that the missionaries do good work. If they had undesirable activities, it has been taken up by Government. They have also done good work. What I am particularly stressing is the

absolute flood of Communist literature that is put into the hands of our students through very colourful pamphlets and books which the Government should look into. There are presses in Calcutta which print them. They get money from foreign sources and they sell them at very cheap rates. I am sure, the hon. Member knows about it too.

SHRI PILOO MODY : Probably printing them.

SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI : The Communist Party prints them. They have the most laudable things to say about China and Russia in them. They say that everything is a bed of roses in China and Russia as compared to India. That is why there is a lot of student unrest here. Those who work in these presses, are highly paid because there is foreign money coming in. I am sure, the spirit of the Bill will be appreciated by the hon. Minister that also he will look into the channels through which arms and ammunition have been coming over the past 10 years creating devastation in the country and opening the doors for a red revolution. Unrest and chaos if it is to come, it will come through those sinister channels. We should be careful and we should look into those channels. Otherwise, India will have to suffer for our negligence.

श्री फ० गो० सेन (पूर्णिया) : उपाध्यक्ष जी, यह विधेयक जो माननीय गुप्ता जी लाए हैं उस का उद्देश्य जरूर महान है। इस बिल को पढ़ने के बाद मुझे एक बात कहनी पड़ती है कि अब हम लोगों को सोचना है कि हम लोगों को जो एड मिलता है वह विद स्ट्रिंग मिलता है या विदाउट स्ट्रिंग मिलता है। बहुत सुनते थे कि एड विदाउट स्ट्रिंग है, मगर जो हालत चल रही है...

एक माननीय सदस्य : मोरार जी से पूछिए।

श्री फ० गो० सेन : जी हां, उन के खिलाफ आप को अगर बोलना हो तो जरूर बोलिए। बल्कि वह तो अब अपोजीशन में हैं उनसे क्या पूछना।

Why can't you bring it now ? He is in the Opposition. Why do you speak of Mr. Morarji Desai when I speak ? What he is to be asked ? You bring charges against him. I challenge you. Why don't bring charges against him ? where are Mr. Chandrashekhar and others who brought charges against Morarji and Birlas. And then Birlas were given that Goa fertiliser project. That is your socialistic pattern of society is not it ? Don't tell me, don't tell me and, again, I say, don't tell me.

तो हम जानना चाहते हैं जो बात उन्होंने कही इस का बड़ा असर पड़ता है। हमारे गांवों के भोले भाले लोग आजकल अखबार पढ़ने लगे हैं। उस में यह बातें भरी रहती हैं कि यह इतना पैसा खा गए, ऐसे पैसा आया, कैसे खर्च हुआ, हिसाब नहीं इतना पैसा इस ने मार दिया, इतना यह खा गए, इस तरह पैसा खाने का और करप्शन का समाचार हम लोगों के बिहार पेपर्स में तो इतना आने लगा है कि हम लोगों के नाकों दम हो गया। रोज कोई न कोई बात निकलती रहती है किसी न किसी के बारे में। अभी एलेक्शन में किस तरह से कहां से रुपया आया ? गवर्नमेंट की रिपोर्ट में जब है कि फारेन मनी आया है, आप ने इसे ऐडमिट किया है तो कहां से कितना आया है, किस ने लिया है यह क्यों नहीं बतलाते ? आज भी संसद के सामने बात आई है कि यह कलचरल सोसाइटी बन्द किया गया। अगर बन्द किया गया है फिर उस में उन्होंने कहा कि बहुत सी बातें ऐसी हैं कि हम सभा पटल पर नहीं रखना चाहते। नहीं रखना चाहते उस के मानी हैं कि दाल में कुछ काला है। अरे, साफ बात रखने में हमारा क्या है, हमारे गांधी जी के रास्ते में कोई दाल में काला नहीं है। साफ बात है।

श्री यज्ञदत्त शर्मा (अमृतसर) : दाल में काला नहीं, बिलकुल काली दाल है।

श्री फ० गो० सेन : इसीलिए वह उसे बताना नहीं चाहते हैं। अभी चाइना बैंक के बारे में निकला था, कितने कितने उसके ऊपर

[श्री फ० गो० सेन]

बवेश्चंस हुए, कहां से रुपया आया, किलट्ज को गया, किस किस को गया, किस तरह गया यह कहीं नहीं बताया गया। तो यह सब चीजें आज चल रही हैं। डेमोक्रेसी आप ने बना रखी है, बड़ा अच्छा है, हम जानते हैं। मगर उस की रक्षा के लिए आप को भी तो कोई स्टैंडर्ड मेनटेन करना पड़ेगा। आप को भी तो कुछ करके दिखलाना पड़ेगा कि यह स्टैंडर्ड है, लेकिन कहां है आप का स्टैंडर्ड ? आप का "जंटिलमैन्स वर्ड इज ए बांड" कहां है यह चीज ? आप का अगर यह स्टैंडर्ड है आप की गवर्नमेंट के, आप के प्रधान से प्रधान लोग अगर अपने वर्ड को नहीं रखते हैं, अपने रास्ते पर नहीं चलना चाहते हैं तो आप दूसरे को क्या बताते हैं कि तुम यह करो, तुम यह करो। आप को क्या अख्तियार है लेक्चर देने का, सरमन्स आन दि माउंट देने का ? आप को कोई अधिकार नहीं है अगर आप का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अरे अधिकार क्या होगा ? आप लोग रहनुमा हैं, आप लोगों के लिए इतना इतना रुपया खर्च होता है आप के कहीं जाने पर। आप लोग जाते हैं एक एक स्टेट में, लाखों लाख रुपया आप के ऊपर खर्च हो जाता है जहां पर कि लोग तरसते रहते हैं, हमीं ने कितनी दरख्वास्त दी है कि उनको कुछ दे दिया जाये। आप लोग स्टेट्स में जाते हैं तो सवाल यह पैदा होता है कि आप लोगों की सिक्योरिटी पर कौन रुपया खर्च करे। मैं जानना चाहता हूँ कि यह रुपया क्यों खर्च होता है। इस के माने यही हैं कि आप लोगों का कोई स्टैंडर्ड नहीं है इसी लिये आपको सिक्योरिटी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। आज ज्योति वसु को भी ज्यादा सिक्योरिटी चाहिये, क्यों इतनी सिक्योरिटी की जरूरत है—क्या मैं पूछ सकता हूँ। इस के माने यही हैं कि आप की जान की ज्यादा कीमत है, बाकी लोग चाहे गोली के शिकार हो जांय--जैसा अभी श्रीमती इलापाल चौधरी जी ने कहा। दो पार्टियों को लड़ा दिया जाय, दो-चार लाश गिर जांय, गिर जाओ, क्या फर्क पड़ता है, इस में पार्टी का क्या नुकसान होता है, इन गरीबों को पीछे कोई देखनेवाला नहीं।

इस लिये मेरा कहना यह है कि आज हम को इस के बारे में सोचना चाहिये। जब जब एड का सवाल आया है, हम को यहां पर कभी साफ जवाब नहीं मिला। मुझे प्रेसवाले माफ करें—यहां बहुत से छोटे छोटे अखबारों के रिप्रेजेन्टेटिव्ज बैठे हुए हैं, उन का खर्च कहां से आता है ? हम लोगों ने तो अपना रिम्युनरेशन बढ़ा लिया, लेकिन क्या आप समझ सकते हैं।...

श्री ज्योतिर्मय वसु (डायमंड हार्बर) : होम मिनिस्टरी में आता है, चव्हाण साहब को खबर देते हैं।

श्री फ० गो० सेन : आपको अख्तियार है, पूछने का, पूछिये। मुझे ज्यादा नहीं कहना है। मैं समझता हूँ कि श्री कंवर लाल गुप्ता जी ने जो बिल यहां पर रखा है, इस का उद्देश्य महान है, मैं इस को सपोर्ट करता हूँ।

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central) : Sir, I entirely agree and appreciate the principle underlying this Bill which has been brought forward by Mr. Kanwar Lal Gupta. He has made a very relevent speech. There is no reason whatsoever either to contradict or oppose what he has said. On the coutrary, I would say that the political, economic and social life of this country is likely to be completly and totally polluted by money and literature whether that money or literature comes either from the West or from the People's Democracies. It should be mentioned that the very fountain of our public national life is sought to be vitiated.

After 1967 elections we had a flood of literature distributed to some of the Members of Parliament. When I waded through that literature, I was surprised and shocked. It appears that our life is being polluted to such an extent that our country is sought to be made another colony by the

thought process, money and literature, indoctrination of our younger generation and young and impressible minds. You will find that the very concept of sovereignty and integrity of our country is sought to be attacked. Therefore, I would say that so far as the principle is concerned, I entirely agree and appreciate that principle. But the remedy does not lie through this Bill.

There are two aspects which ought to be kept in view by every Member of Parliament. One is the educative aspect. Our Public men are generally honest but some persons need to be re-educated first, as to the danger of getting foreign aid and foreign help and money and literature which is sapping the moral basis of the Indian society. This is one aspect of it.

The second aspect is this. The law also could be changed to bring about some changes and punitive measures. But, then, I am told, the Government would like to bring forward a comprehensive measure which will deal with this aspect of the foreign aid through money and literature, etc. so that these things could be stopped. There is one more thing which I would say in this connection. I do not know whether it is any unique phenomenon in our country. As we study some aspects of the history of these South-East Asian countries, and the freedom movement of these countries, we see, this phenomenon is found everywhere. No country is free from it, and it is there in world politics, in international politics. We, the publicmen ourselves and those who can influence and change the minds of our younger generation have a very historical. important role to play, so that our Nation can occupy very prominent and important place that is due to us in the comity of nations.

Therefore I would like to urge on Mr. Gupta about this aspect. I do not want to be vociferous. We need not give illustrations. But upon every Member of Parliament, I would urge that they may study this problem in all its aspects and Government should also not hesitate to bring in a comprehensive legislation in this record. We have been hearing something about the report which was submitted to the Home Minister and some enquiry made through their agencies to find out the resources which certain political parties and different machineries and educational institutions got money by way of foreign aid in order to pollute the Indian life. At the time of elections, not only the minds of some of our public men are conditioned by such aids, but even the elections are sought to be so governed, guided, and controlled that some Members may not be elected at all. That was also sought to be done at the time of last general election.

Therefore, I would urge that the Government should lose no time in bringing up such a comprehensive legislation so that there could not be such tie of international forces which seeks to colonise our country. Such attempts should be stopped in time so that our life political and Public life—will be pure in its prestine glory and purity so that democracy will be preserved in this country, and the sovereignty and integrity of our country could be kept in tact. I think that is also the mind of the Government as far as I am able to know about the incling in the mind of the Government. Therefore, I request Mr. Kanwar Lal Gupta about this. We having accepted the principle, appreciated his view point, having agreed to widen the scope of the principles, he should withdraw the Bill, becasuse, how many clauses are there ? I would request him to see how many clauses are there in the Bill Are these clauses sufficient.

SHRI BAKAR ALI MIRZA (Secundarabad) : Why Mr. Masani.

SHRI R. D. BHANDARI : Because he was just laughing at this. I would have appreciated his smile. But it appears to be cynical—I may be wrong.

SHRI PILOO MODY ; He has a neutral laugh.

SHRI R. D. BHANDARE : Therefore, what I would call this 3-clause Bill will not meet the needs of the times. I would request Government to bring forward a comprehensive measure so that all the ills could be removed and our life could be preserved in its pristine purity in terms of democracy, integrity and sovereignty of our country.

SHRI N. K. SOMANI (Nagaur) : Having listened to the burden of the arguments placed before us by Shri Gupta and having given considerable thought to the structure and intention of the Bill, I am constrained to oppose it entirely.

[Shri N. K. Somani]

I for one believe that this Government, particularly the Home Ministry, has wide enough powers not only to contain any nefarious or anti-national activities but also whatever is likely to corrode or corrupt our national life. For that matter, we have said on the floor of the House several times that it is not as if the Home Minister does not know the role foreign money played in the last elections and at some other times. Only it is not convenient for him to place those facts before us,

If Shri Gupta had come forward with a plea that all political parties in India should have a compulsory audit and should disclose the sources of the money they have received, we would certainly have been the first to support such a proposal. If he had also cited certain concrete examples where the extent and scope of the influence is so much that it has become a danger to the sovereignty of the country or our national interests, we would have gone all along for that. But I think he has brought to our attention certain isolated examples. Howsoever obnoxious they are, to my mind they are very few and for the sake of a few black-sheep in every society including ours, I do not think it is fair to voice condemnation in such a sweeping and general manner to the extent of saying that all the social, cultural, economic, political or other activities in our policy should be put into a straight-jacket.

I would like to start with the Christian missionaries. I think there is some kind of a pathological hate...

AN HON. MEMBER : Fear.

SHRI N. K. SOMANI : Not fear, may be obsession, with them. I would like to say that these Christian missionaries have done wonderful work in this country. In my own constituency which is predominantly Hindu, through a Christian society for the last one or two years we have been doing extremely valuable, humanitarian work where the Government of Rajasthan and the Government of India have failed to bring food to the people in times of famine. I can say on the floor of the House that not a single person has been converted either into a Christian or an anti-national as a a result of C.A.S.A. activities.

I can cite other examples. Probably the Home Minister is a little prejudiced towards Fr. Ferrer. We know about his activities intimately. Both Shri Piloo Mody and myself had spent several hours with him in Manmad. When he was forced to leave that place, thousands of peasants had tears in their eyes. I can tell you that he is now doing very wonderful work in the Rayalseema area of Andhra Pradesh.

Therefore, to make sweeping generalisations in condemnation of these activities is unfair. Of course, there have been black sheep amongst them. But we expect that the Home Ministry to be is powerful enough, alive enough and keen enough to isolate such elements from the mainstream of our life.

Take the other point of view. Who was Swami Vivekananda if he was not a missionary, when he went to the US ? Who is Maharshi Mahesh Yogi who has been spending the the last two or three years going everywhere round to every other country ? Should they shut the door to our missionaries also who are actuated by the purest spirit of goodwill, not only to propagate their own religions, but also to try to understand what other religions teach ? Swami Ranganthananda of whom I know well, of the Ramkrishna Mission International, travels eight to nine months in a year propagating the ideals of Hindu culture and of the Mission. If the doors of the rest of the countries are going to be closed to such missions, I do not understand how this problem is going to be solved at all.

Take the instance of the 1962 Chinese aggression. Mrs. Leela Moolgavnker of the Tata Blood Bank came desperately to me because she wanted an equipment which would very rapidly make a sample blood test and would in a minute analyse the blood of 50 people. Blood was required very urgently. I cabled some friends in Los Angeles and within a few days that equipment came. There are instances like this and institutions get help for the crippled or handicapped or blind people or for research in leprosy, family planning, etc. they receive receive not only valuable research material, but even money. Why should all this be stopped ? Of course, I expect them to be registered under the Indian Societies Act or whatever other rules, to keep their accounts and to circulate them to their own members,

trustees, office-bearers, etc. but I cannot see for the life of me, unless of course there is something serious found against them, and the Home Minister has got enough powers to find this out, why they should be put under such requirements. We are taking as if our coontry has become very affluent not only materially but al-o in scientific, technological and humanitarian terms. Not only that. Towards the end of the Gandhi Centenary Year it would seem that we would like to choke and put in a strait-jacket all the cultural activities that are sought to be brought in through various associations, institutions, etc. and shut our doors to them. This I would call McCarthyism of a very foul kind.

If I receive some Soviet money or Chinese money, I certainly cannot be expected to go to the Home Minister and disclose to him the sourse and say that I have received so much money and that I am going to use it for this purpose. Therefore, that purpose is not going to be served by the Bill at all. On the contrary, voluntary organisations which are getting research grants, scholarships, etc., will be damaged by this.

If he had said, for instance, that there should be a quasi-judicial board to look into the administration of the entire Rupee trade where we hear all kinds of complaints, we would certainly have given further thought to it. If he had said that societies like the Indo Soviet Friendship Society should be registered under the Indian law and that its members as well as the Government or the Registrar of the Societies should receive the annual accounts and the report of their activities every year, we could have very well supported that move. Such societies and such activities are allowed today not to be regulated and go the way they want. On the contrary, this extremely unpleasant proposition is brought in. I would therefore like to say that I do not think that for the sake of a few black-sheep which he has mentioned, and there are other examples also, any sweeping generalisation and accusation against our national character or integrity is deserved on the floor of the House. Therefore, on this basis we would like to oppose this Bill.

SHRI BEDABRATA BARUA (Kaliabor): It is good that Mr. Somani has slightly changed the perspective and raised certain very pertinent objections to this Bill.

I think by and large the spirit of the Bill is good and I do not share Mr. Somani's enthusiasm for these cultural and academic institutions. I do not also share Mr. Gupta's antipathy for foreign ideologies. I think we in India had never at any time closed our doors to ideas from the outside world.

It never occured to us that an idea could finish or destroy the very resistant-fabric of our society. An American sociologist says that India has shown the capacity for survival, which has been surpassed only by China. Mr. Selig Harrison has written that famous book, ***India the most dangerous decade***. It is a book of 500 pages in which he analyses the centrifugal forces in Indian society. It is very interesting to read that book. He has gone into all the sub-nationalist urges in the Indian society, 3,000 years of Tamil history as it was claimed, Malayalam, Canarese urge for having separate indedendent history, history of conflict rather than of co-operation. This book is an example of how they look at India. Foreign academicians who come to India for studying the country give their conclusions in the final chapter and say that it should be the objective of western powers to encourage it. In his book Selig Harrison concludes that possibly India would have to go through a temporary period of dictatorship and that the objective of western power should be to see that it is not the dictatorship of the left but the dictatorship of the right because he says that this civilisation which resisted all types of divisive forces will still resist them and this resistance will culminate in a synthesis where the fissiparous tendencies will not gain an upper hand in the country. When we think in terms of foreign ideologies, we should speak of Rebindra Nath Tagore's teaching : we would like fresh winds to blow into my room but I would not like to be swept away by the impact of those waves of air. I think we should have no objection for anybody preaching their ideologies here. Let the Americans have their laissez faire theory or their brand of freedom or the Russians their brand of communism. India has always been able to synthesise them. I do not want to be sentimental.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I do not mind if you have their ideologies, but not their money, foreign money.

SHRI BEDABRATA BARUA : We can send our leaflets to foreign countries and we do not want to charge them, if possible. I do not mind the Russians giving free literature or the Americans giving free literature...(*Interruptions*) Why should any brain be washed ? After all do we not have a civilisation which is as old as any in the world ? If ideas flow into our country, our people are not automatically influenced. The wave of modernism, with all the twist and all those things have come. If foreign ideas get a foothold here, it is not because the ideas are stronger or are financed by somebody : they get a foothold because of our resistance to it becoming weaker ; that shows the decadence in society... (*Interruptions*) Aristotle bemoaned what happened in Greece. The whole of Greece was divided. Hundreds of petty cities were divided into principalities. There was the aristocratic type of civilisation in Sparta and the democratic structure of Athens. Because of this, the hundreds of small cities or principalities went with one or the other camps and ultimately the whole of Greece fell divided. And there will be an agent functioning inside their cities to welcome them. What happened in Greece ? the whole structure of beautiful cities collapsed one after another. Not even Athens could survive the load of all those crises. Has that period passed in this world ? At least during tht last one decade, it has become quiet clear what has happened elsewhere, whether it is Czechoslovakia or Hungary or the Dominican Republic. You can have big friendship with big powers, but unless you are strong enough to resist them, they would try to put their hand on your neck. Nobody is civilised that way. International politics is not particularly civilised. If they get a grip of the economy in the country, over the financial structure, over its political life, if they can get some agents planted inside that country, it is certainly a very serious danger to the independence of that country.

I do not want to make wild allegations that some people make. I do not believe in allegations. Secondly, I do not believe that all those allegations are true. I do not think that the situation has become as bad as that. And surely I do not think that the solution will be really equal to the situation. The situation has different facets. When foreign money comes in, it does not announce its coming, as Shri Somani said. We will have to find out how this money can be prevented from coming in. So, it is basically a question of public opinion. We have to build public opinion. The Government has to go into the details of this method. P.L. 480 funds have been flowing into this country ; this fund has been misused. We all know that it has been misused. We can cite instance. But it is no good citing instances because instances may create only more nervousness without our being able to resist it. This Parliament, the Members of Parliament, the people who are in charge of promoting goodwill in the public life of the country today must develop a regular contempt for this type of things. We must in our own private lives refuse to be guided by being bribed by this process, especially in India which is a poor country. I have found in several other poor countries also, even in the West, and elsewhere, that they have made mincemeat of their democracy. I do not think any national independence can survive this type of inroad if a country gets divided into supporters of one group or the other. It is not possible to resist that type of inroad.

So, I think that while this Bill is not possibly a solution, there is necessity for some sort of serious enquiry into this matter to find out exactly how much we have been suborned, how many people have been influenced and how many people really do get foreign money. These things are important, and these things have to be resisted.

These things have happened in Britain also. Some Members of the British Parliament were reported to have got bribes, this and that. There was a big enquiry, and it was found that some Members of Parliament were found working for foreign interests. After they discovered it, it became a pretty big scandal in Britain. They tried to put an end to it. Sometimes discussion is good and sometimes discussion may be spoiling the public life too much. I do not think there should be too much discussion, but, at the same time, it is necessary that we must develop pockets of resistance to these things. Unless we do that, merely talking will not do.

We have been friends with the Soviet Union and we are friends with the U.S.A. I would like friendship with them to

continue. At the same the, let us see the friendship of Nasser or Tito with others; while they have friendship with some other countries, they have seen to it that inside their country there are no pockets of other powers.

I think basically this is a question of national sovereignty. We will certainly survive this type of affairs. It is an insult to the poverty of our country that big powers sometimes try not only to have friendship but do some other things. Let them cultivate friendship and let them have cultural missions and the like here if they like; let them also try to assure us that their system is as good as ours: when we go outside, we also try to show that our system is as good as theirs if not better, though diplomatically it is not good to say so. Many powers may say that but saying that may not be much. But we develop resistance to this and build up public opinion.

17.00 hrs.

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : इस विधेयक में मैंने आशा की थी कि कुछ कारगर रास्ता भी इसका बताया जाएगा लेकिन इस में विदेशी धन को रोकने की बात नहीं कही गई है, उसको रोकने का कोई उपाय भी नहीं बताया गया है, उसका प्रयास तक भी नहीं किया गया है, केवल मात्र यही बताया गया है कि विदेशी रुपया जो आए उसका हिसाब किताब कैसे रखा जाए।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, इसकी नजर में, इसकी धाराओं की नजर में विदेशी रुपया लेना गर्हित नहीं है, निन्दनीय नहीं है, हिसाब उसका नहीं रहता है, यही निन्दनीय है। हिसाब किताब ठीक से रहे विधेयक के जरिए इसी सवाल पर विचार किया गया है और इसी सवाल पर विचार करने का हमें मौका मिल रहा है। विदेशी रुपये के चलते क्या हमारी राजनीति पर, क्या हमारी अर्थ नीति पर, क्या हमारी विचार धारा पर और क्या हमारे जनतन्त्र पर प्रभाव पड़ता है और कहां तक हमारा ईमान बेचता है, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। आज हम देखते हैं कि पैसे पर ईमान बदलता है। लेकिन ये सब पहलू हैं जिन पर हमें विचार करना होगा और अगर हमने ऐसा किया तो मैं समझता हूं कि कुछ ज्यादा व्यावहारिक नतीजे पर हम पहुंच सकेंगे।

मैं नहीं समझ पाया हूं जब कोई सदस्य कह देता है कि अमरीकी विचारधारा से हम विदेशी हैं या सोवियत संघ की विचारधारा से हम विदेशी हैं। हम भारतीय जानते हैं कि एक समय था जब हमारे देश में अमीर गरीब का फर्क नहीं था, राजा प्रजा का फर्क नहीं था। उस जमाने को सत्युग कहा जाता है। उसे समाज शास्त्री आदि समाजवाद कहते हैं। उस समय अगर कोई भूखा सो जाता था तो वह चोर कहलाता था। यह मैं अपनी बात नहीं कहता हूं। यह ग्रन्थों में लिखा हुआ है। रूस वालों की सभ्यता बहुत बाद की है। अमरीकी सभ्यता का जहां तक सम्बन्ध है वह तो और भी बाद की है। हमारी सभ्यता तो बहुत पुरानी है। हमारी प्रचीनतम सभ्यता यह थी कि समाज में कोई अमीर गरीब न रहे, कोई व्यक्तिगत सम्पत्ति का स्वामी न रहे। यह बात अगर आज भी होती है तो यह भारतीय संस्कृति और भारतीय परम्परा के अनुकूल होगा। तुलनात्मक रूप में हाल के ग्रन्थों में श्रीमद्भागवत, उससे पहले महाभारत और उससे पहले ऋग्वेद छपा था।

भागवत में यह है :

यावत भ्रियते जठरम् तावत स्वतम् हि देहिनाम
अधिकम योभि मन्यत् सः स्तेन दण्ड मर्हति

जो पेट भरने से रह जाता है वह चोर है और दंड का भागीदार। मैं समझता हूं कि जो पूंजी के रक्षक हमारे देश में हैं वे समता की बात को विदेशी समझ लेते हैं। जब वे ऐसा करते हैं तो और बातें जो वे चाहें कहें लेकिन भारतीयता का दावा वे न करें। पुरानी सभ्यता पूंजी की पुजारी नहीं थी, लेकिन आज देश उसका पुजारी हो गया है। इंग्लैंड के पूंजीवाद

[श्री भोगेन्द्र झा]

ने हम को गुलाम बना कर रखा। हम ने उसको पूंजीवादी जनतन्त्र का रूप दिया। हमारा जनतन्त्र पूरा जनतन्त्र नहीं है, पूंजीवादी जनतंत्र है। चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति यह बता सकता है कि रुपये के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचा जा सकता है। यह जो जनतांत्रिक पहलू है, इसको तो हम मानें लेकिन पूंजीवाद वाला पहलू है इसको न मानें क्योंकि यह बाधा उपस्थित करता है, यह रुकावट पैदा करता है, हमारे देश की सभ्यता के विकास में, हमारे देश के विकास में। ऐसी स्थिति में कौन कौन से ठोस रूप हैं जिन रूपों में विदेशी धन, अर्थ आदि हमारे तन्त्र या तन्त्रों को प्रभावित करते हैं, हमारे ईमान को खरीदते हैं।

17.03 hrs.

[**Shri K. N. Tiwary** *in the Chair*]

मेरी राय में सदन इस पर विचार करे कि क्या सबसे बड़ा जरिया, सब से बड़ा साधन वह नहीं है जो देश में विदेशी कारोबार से रिश्ता जोड़ता है। मैं इसको दोगला पूंजीवाद कहूंगा। यह हमारे देश में पैदा हुआ है। संयुक्त कारखाने हम बना रहे हैं और वे जायज तरीके से भी बन सकते है, उसका एक हिस्सा जायज भी है और वह यह है जहाँ विदेशी हिस्सेदार रहते हैं। मैं उसकी बात नहीं करता। लेकिन आप देखें कि पिछले साल इण्डियन एयरलाइन्ज की बात पकड़ी गई थी। उसके बारे में जो चिट्ठी थी उसकी काफी यहां पर रखी गई थी। वह अकेली घटना नहीं है। ऐसी घटनायें बड़े पैमाने पर होती हैं। हम लोग इसको मानते हैं। देश का एक बहुत बड़ा इजारेदार तबका विदेशी करोड़पतियों से सांठगांठ किये हुए है और वह राष्ट्रीय उद्योगों के विकास में बाधक साबित हो रहा है, राष्ट्रीय अर्थ तंत्र के विकास में बाधक हो रहा है। अगर कहीं अमरीकी कह दे या विश्व बैंक कह दे कि योजना बन्द हो जाए तो हमारे अखबार कहने लग जाते हैं अधिकांश कि प्लान हालिडे हो जाए। उसे हम अपमान नहीं समझते हैं। अगर कहीं अमरीका कह दे कि तुम्हारा आकाश को हम ले लेंगे तो ये कहते है कि हम को अम्ब्रैला मिल गया है, अमरीका हम को छतरी दे रहा है। यह नहीं कहते हैं कि यह एक कलंक की बात है कि एक देश हमारे आकाश में दखल देने की मांग कर रहा है। मैं आग्रह करूंगा कि आप इस पर विचार करें, किस विचारधारा पर जायें, उस पर बाद में आएं।

सदन में विभिन्न विचारधाराओं वाले अखबारों का जिक्र आया है। मैं अपवाद करना नहीं चाहता हूं। लेकिन अखबारों पर यह असर है और खास कर जो अखबार करोड़पतियों के पंजे में हैं, उन पर पूंजी का असर पड़ता है। दो दिन पहले लाओस के मामले पर यहाँ एक ध्यानाकर्षक का प्रस्ताव आया था और उस पर हमने बहस की थी। अमरीकी अखबार और अमरीकी रेडियो कहता है कि अमरीका का खुफिया विभाग, सी०आई०ए० एक कम्पनी के हवाई जहाज ले कर वहां बमबारी कर रहा है। लेकिन सदन में हमने बहस की कि उत्तर वियतनाम हमला कर रहा है। वह भी हिन्द चीन का हिस्सा और दूसरा भी हिन्द चीन का हिस्सा। सी०आई०ए० वहां पर हमलावर नहीं है इसको बताया जाता है। प्रतिष्ठित अखबारों ने इस प्रकार का फीयर पैदा कर रखा है।

मैंने दोगला पूंजीवाद कहा। यह एक बहुत बड़ा जरिया है। इसके रहते हम विदेशी अर्थ पर लगाम लगाने में कहां तक आगे बढ़ सकते हैं, इस पर आप विचार करें। दूसरे जो हमारी पुरानी नौकरशाही है जिन्होंने गुलामी के दिनों में विदेशों से प्रशिक्षण पाया, उसको भी आप देखें। उसको आप बुरा नहीं मानते हैं। आपने विलायती कानून पढ़ा है। प्रस्तावक महोदय श्री गुप्त को भी विलायन की बात बुरी नहीं लगी। विलायत का उन्होंने नाम तक नहीं लिया।

दो सौ साल की गुलामी में वह विदेशी भी स्वदेशी बन गया। चार का नाम गिनाया लेकिन दो सौ साल की गुलामी ने विदेशी का भी स्वदेशी बना दिया। और भी आप देखें। हम सब जानते हैं कौल के बारे में हंगामा हुआ था। कृष्ण मेनन को श्री नेहरू ने हटाया था क्योंकि वह चीन के प्रति हमदर्दी रखते थे, ऐसा कहा गया था। लेकिन उन्हीं को जापान में अमरीकी कम्पनी के द्वारा एक उच्च पद प्रदान कर दिया गया और ऐसा बरखास्तगी के कुछ ही महीने बाद कर दिया गया। उन्होंने एक किताब छापी। मुल्क में वह बिक रही है और लोग उसको पढ़ रहे हैं। एक उच्च फौजी अधिकारी जिन का नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, उन्होंने अपनी किताब में खुद लिखा है कि बीस साल तक मैं अमरीकी पूंजीवाद के सब से बड़े अखबार का गुप्त युद्ध संवाददाता था। हमारे फौजी अफसर जिन का कोर्ट मार्शल होना चाहिये, अभी भी उच्च पदों पर आसीन हैं। दूसरे अफसरों का पहलू है। तीसरे अखबार का पहलू है। हमारे गुप्त जी गौर करें कुछ साल पहले खुद आर्गेनाइजर और पांचजन्य के सम्पादक अमरीका गए थे। मैं जानना चाहता हूं कौन सी बात सीखने वे गए थे? क्या पत्रकारिता सीखने गए थे? अमरीकी सभ्यता सीखने या देखने गए थे। लेकिन अमरीकी सभ्यता तो चार सौ साल पुरानी है। उससे पहले की अमरीकी सभ्यता को अमरीकियों ने मिटा दिया है, मनीषियों को भी मिटा दिया है। अखबारों के जरिये भी बुरा प्रभाव पड़ता है, वे हमारे ईमान को विकृत करते हैं, हमारी समझ को भी विकृत करते हैं।

चौथे राजनीतिक पार्टियों की बात आती, राज नेताओं की बात आती है। चारों तरफ से हम प्रभावित हो रहे हैं और करोड़पतियों के अखबार भी राजनीतियों की बात करते हैं तो कुछ को छोड़ देते हैं। एक शब्द भी श्री मोरारजी के बारे में प्रसारित नहीं किया गया। अमरीकी गुप्त एजेंसी का जो युवक संगठन था उसके प्रधान वह थे। इसको उन्होंने प्रसारित नहीं किया इस वास्ते चूंकि उनका अपना रिश्ता उससे था। लेकिन फिर भी राजनीति को बदनाम करते हुए क्या फौजी तानाशाही का रास्ता आप साफ नहीं करते हैं? फौजी तानाशाही फौज के जवान ही स्थापित नहीं करते हैं, वह करोड़पतियों की भी होती है, विदेशी सांठगांठ से भी हो जाया करती है। राजनीतिक भ्रष्टाचार इसका एक हिस्सा है। चार में से एक हिस्सा है।

मैं आग्रह करूंगा कि हम चाहे हम किसी भी विचाराधारा या दल के हों, इस पहलू पर विचार करें। चार इसके मुख्य स्रोत हैं। पांचवां भी हो सकता है। उस पर भी विचार हो, हमें एतराज नहीं है। इन सब स्रोतों को हम बन्द करें, उन पर चोट करें। यह जिससे सम्भव हो सके, उसको आप यहां रखें। हमारी जो समाज नीति है, हमारी जो अर्थ नीति है, वह जिस तरह से आज प्रभावित हो रही है उस पर किस तरह से लगाम लगाई जा सकती है, इसके बारे में विचार करना और उपाय करना हम सभी का लाजिमी कर्त्तव्य हो जाता है।

मुझे निराशा इस बात की है कि यह विधेयक उसमें से किसी का भी प्रयास नहीं करता है। केवल हिसाब रखने की बात इसमें कही गई है। विधेयक उसको पूरा करने का प्रयास भी नहीं करता। प्रयास की बात तो दूर उस पर प्रकाश भी नहीं डालता। मैं गृह मन्त्री से आग्रह करूंगा कि वह ऐसा रास्ता निकालें कि विदेशी धन हमारी राजनीति को, हमारे ईमान को जहां प्रभावित करे, उसके खिलाफ कारगर कदम उठाये जायें। उन कारगर कदमों को उठाये बगैर हम ईमान और बेईमान में फर्क नहीं कर पायेंगे, अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर पायेंगे। इसका कोई रास्ता निकालने के लिये अगर कोई विधेयक लाया जाएगा तो उचित होगा और हम उसका स्वागत भी करेंगे।

श्री तुलशीदास जाधव (बारामती): सभापति महोदय, माननीय सदस्य, श्री कंवर

[श्री तुलशीदास जाधव]

लाल गुप्त, इन्होंने जो बिल रखा है, उसमें तीन बातें कही गई हैं : व्यक्तियों और संस्थाओं को जो मदद मिलती है, उसका हिसाब रखा जाये ; वह हिसाब सरकार को भेजा जाये और सरकार उस हिसाब को पालियामेंट के सामने पेश करे। माननीय सदस्य ने इसका कारण यह बताया है :

> "Such aid is received even through some foreign missionaries in India. Such aid is utilised to influence the cultural, economic, political, religious and other activities in this country. This adversely affects the sovereignty and independence of the country. It is, therefore, necessary to keep Indian life and politics away from outside influence."

मेरी समझ में नहीं आता कि जो कुछ माननीय सदस्य चाहते हैं, वह कैसे सम्भव होगा। दूसरे देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने के लिए इन्डो सोवियत कल्चरल सोसायटी और इण्डो-जर्मन कल्चरल सोसायटी जैसी कुछ संस्थाएं यहां काम करती हैं जैसा कि स्वतन्त्र पार्टी के माननीय सदस्य ने कहा है रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानन्द दूसरे देशों में हमारे धर्म और संस्कृति के प्रचार के लिये गये थे और आज भी रामकृष्ण मिशन कई देशों में काम कर रहा है। उनके बारे में तो ऐसा कोई सवाल नही उठाया गया।

श्री कंवरलाल गुप्त : इनको कुछ तो समझ होनी चाहिए। यह स्वामी विवेकानन्द का मुकाबला फारेन क्रिस्चियन मिशनरीज के साथ कर रहे हैं। इनको कुछ शर्म आनी चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री यमुना प्रसाद मंडल (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, इस सदन में एक माननीय सदस्य किसी दूसरे माननीय सदस्य के विरुद्ध में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करे, यह ठीक नहीं है।

श्री तुलशीदास जाधव : मुझे इस बात का दुख है कि माननीय सदस्य बात तो धर्म और संस्कृति की करते हैं, लेकिन इस आगस्ट हाउस में ऐसे शब्द उच्चारते हैं, जिन्हें रास्ते में दो गुंडे उच्चारते हैं। "किसी को शर्म नहीं है" या "तुमको अक्ल नहीं है," पालियामेंट में इस तरह के शब्दों का प्रयोग शोभनीय नहीं है। अगर मैं भी उसी प्रकार के शब्द कहूँ, तो ठीक नहीं लगेगा। **(व्यवधान)**

श्री शिव नारायण (बस्ती) : माननीय सदस्य ने कह तो दिया।

श्री कंवरलाल गुप्त : माननीय सदस्य ने बहुत अच्छे शब्द का उच्चारण किया है।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : 'गुंडा' शब्द एक्सपंज कर दिया जाये।

श्री तुलशीदास जाधव : मैंने बाहर रास्ते की बात कही है, यहाँ की नहीं।

बाहर से जो पैसा आता है, अगर उसका उपयोग गलत कामों के लिए किया जाता है, तो सरकार और होम मिनिस्ट्री को उसकी रोकथाम करनी चाहिए। माननीय सदस्य चाहते हैं कि इस देश को कल्चरल, इकानोमिक और पोलिटिकल स्फीयर्ज में दूसरे देशों के प्रभाव से बाहर रखा जाये। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। आज दुनिया में साइंस और टैकनालोजी इतनी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन माननीय सदस्य चाहते हैं कि इस देश को उससे अलग रखा जाये। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि कल्चर या एजूकेशन के नाम पर हमारे देश पर किसी अन्य देश द्वारा दबाव डाला जाये। लेकिन माननीय सदस्य और उनकी पार्टी जो बार-बार क्रिस्चियन मिशनरीज मुसलमान हरिजन और दूसरे लोगों के खिलाफ प्रचार करती है, उससे मुझे बड़ा दुख होता है और शक भी होता है।

आप जानते हैं कि जैन धर्म में "स्याद

वाद" को माना जाता है, जिसका अर्थ यह है कि दूसरों में भी कुछ सच्चाई हो सकती है। सभापति महोदय, आपके आसन के उपर बौद्ध धर्म से प्रेरित "धर्मचक्र प्रवर्तनाय" लिखा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि धर्म का प्रचार और प्रसार सभी जगह हो। पार्लियामेंट हाउस के गेट नम्बर 1 से आते हुए सेंट्रल हाल के द्वार पर आपने यह श्लोक भी देखा होगा : "अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम्, उदारचरितानाम् तु वसु धैव कुटुम्बकम्" इस आदर्श को मानने का दावा करने वाले लोग यहां पर किसी न किसी निमित्त क्रिश्चियन्ज, मुसलमानों और हरिजनों आदि के खिलाफ बार-बार बोलते हैं, इससे हमें बड़ा दुख होता है।

अगर माननीय सदस्य यह कहते कि इस देश पर अन्य देशों का पोलिटिकल इनफ्लुएन्स न हो, तो वह बात मेरी समझ में आ सकती थी। लेकिन क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि जिस कल्चर में इन्सान इन्सान में भेद भाव किया गया है, एक आदमी को ऊंचा और दूसरे को नीचा समझा गया है, उस कल्चर को बनाये रखा जाये और उन्हीं मान्यताओं को जारी रखा जाये ? मैं उनको कहना चाहता हूं कि दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है और इसलिए उन्हें भी बदलना होगा।

जहां तक इकानौमिक क्षेत्र का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य की इकानोमी की कल्पना फ्यूडल सिस्टम की होगी, जिसमें यह समझा जाता है कि मनुष्य को दौलत भाग्य से प्राप्त होती है, लोग गरीब या अमीर भाग्य से हैं। अगर माननीय सदस्य आज भी इस सिद्धांत का प्रचार करना चाहते हैं, तो न तो हिन्दुस्तान में और न ही बाहर कोई उनकी बात को सुनने वाला है।

जहां तक पोलिटिकल क्षेत्र का सवाल है, संसार मे भिन्न-भिन्न विचार-धारायें चलती है। औरत को जिस तरह से पहले जमाने में मकान में बन्द करके पर्दे के अन्दर रखा जाता था, आज वह नहीं हो सकता है। जहां तक रिलिजस प्रभाव का सम्बन्ध है, जैसे-जैसे दुनिया बदलती है, जैसे-जैसे टाइम बदलता है, जैसे-जैसे विचार और आचार भी बदलते हैं। यह नहीं हो सकता है कि बाहर का किसी प्रकार का कोई इनफ्लुएन्स यहां न पड़े।

माननीय सदस्य ने अपने स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स एण्ड रीजन्ज में कहा है कि इंडियन लाइफ़ को बाहरी प्रभाव से अलग रखना जरूरी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन के मन में इंडियन लाइफ़ की क्या कल्पना है। आज संसार के सब देश एक दूसरे के इतने नजदीक आ गये हैं कि एक दूसरे के रहन-सहन और विचारों आदि का प्रभाव पड़ना अनिवार्य है। आज हम दो-चार घंटे में अमरीका और इंगलैंड पहुंच जाते हैं। इसलिए वहां के रहन-सहन और विचारों का हम पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। आज के युग में इस देश को, या किसी अन्य देश को, एक अलग कम्पार्टमेंट में बन्द रखना सम्भव नहीं है।

माननीय सदस्य ने कहा है कि बाहर से जो मिशनरी आते हैं, वे अपने पैसे से यहा के लोगों पर असर डालते हैं। क्या हम लोगों के विश्वास और मान्यतायें इतनी कच्ची है कि दूसरे लोग इतनी असानी से उनको प्रभावित कर देते है ? यदि हमने यह व्यवस्था की कि बाहर के लोग इस देश में आ कर काम न कर सकें तो दूसर देश भी ऐसा ही करेंगे।

अगर विदेशी धन का यहां पर कोई बुरा परिणाम होता हो, तो उसकी रोक-थाम के लिए साधारण कानून मौजूद हैं। जिस तरह माननीय सदस्य प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के बारे में कहते हैं कि अवांछनीय कार्यवाहियों को रोकने के लिए साधारण कानूनों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है, उसी तरह विदेशी धन के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए क्यों न देश के साधारण कानूनों से काम लिया जाये। कई ऐसे कानून हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : कौन से कानून हैं ?

श्री तुलशीदास जाधव : होम मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि कौन से कानून हैं ।

पुस्तकों और अन्य प्रकाशनों के बारे में माननीय सदस्य ने कहा कि बहुत कीमती पुस्तकें यहां पर बहुत सस्ते दामों पर बेची जाती हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि अगर ऐसा सस्ता साहित्य यहां पर आता है, जिस को गरीब लोग भी खरीद कर पढ़ सकते है, तो उस में आपत्ति की क्या बात है । अगर माननीय सदस्य जैसे लोग कोई पुस्तक लिखें, जिसकी कीमत पन्द्रह रुपये रखी जाये, तो कितने लोग उसको पढ़ पायेंगे ?—मामूली आदमी तो उसको नहीं पढ़ सकेंगे । माननीय सदस्य ने जो आर्ग्युमेंट्स दिये हैं, उनके पीछे तो मुझे उनका कोई और ही उद्देश्य मालूम होता है । यहां पर जो सस्ता साहित्य आता है, गरीब आदमी उसको पढ़ सकता है और उससे वह अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकता है, अपने विचारों में सुधार कर सकता है, दूसरों के विचारो और अपने विचारों की तुलना कर सकता है । केवल हमारे ही विचार सच्चे हैं और दूसरों के विचार झूठे हैं, माननीय सदस्य यह मत कहा से लाये हैं ? यह मत न तो कुरान शरीफ में है और न ही गीता और वेद में है । यह विचार उनके और जनसंघ के सिर में पैदा हुआ है, जिससे देश का बड़ा नुक्सान हुआ है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : आप को चव्हाण साहब कांग्रेस का सिर मानते हैं क्या ? आप को कोई मानता ही नहीं ।

श्री तुलशीदास जाधव : आपके बोलने में मैं कोई बाधा नहीं डालता तो आप क्यों डाल रहे हैं ? मैं आपको उत्तर दे सकता हूं, लेकिन टाइम की वजह से नहीं दे सकता हूं ।

मेरा कहना यह है कि धर्म के नाम पर...

श्री कंवर लाल गुप्त : इसमें धर्म कहां से आ गया ?

श्री तुलशीदास जाधव : अरे भाई, कल्चरल के माने क्या समझते हैं आप ? इसमें यह सब आता है...

सभापति महोदय : आप चेयर को ऐड्रेस कीजिये ।

श्री तुलशीदास जाधव : सभापति महोदय, मैं आपसे विनती करता हूं कि इनको कंट्रोल में रखिए आप ।

सभापति महोदय : आप ईल्ड मत कीजिये बोलिए । और कंवर लाल जी, आप उनको बोलने दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए ।

श्री तुलशीदास जाधव : दूसरी बात उन्होंने कही कि यहां के कई अफसर भी कुछ अमेरीका को बिके हुए हैं पैसे में । मैं कहता हूं आप एक बड़े माननीय सभासद हैं । जो दिल में आए जैसे रास्ते में बोलते रहते हैं ऐसे ही पार्लियामेंट में भी बोलते रहें, यह तो बड़ी अनुचित बात है । पार्लियामेंट में तो जरा समतोल करके सोच समझ कर के बोला करिए । कल को कोइ सवाल आ जाय, कल को कोई अफसर, खैर नाम तो नहीं लिया लेकिन कोई सवाल उठ जाय तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा, कोई कागज है आपके पास जिसके आधार पर आप यह बात करते हैं, कोई प्रमाण है आपके पास ? तो इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए जैसे एलेक्शन के प्रोपेगेंडा में बोलते हैं, यह बोलना ठीक नहीं हैं । और यह कहना बुरी चीज है, इतने अफसर यहां पड़े हुए हैं दो चार लाख, उसमें कुछ ऐसे हों...(व्यवधान)...कोई पोलिटिकल पार्टी का ज्ञानी कार्यकर्त्ता चाहे वह छोटा से छोटा कार्यकर्त्ता हो लेकिन ज्ञानी कार्यकर्त्ता कभी गलती से भी ऐसी बात नहीं करेगा...

श्री कंवरलाल गुप्त : आन ए प्वाइंट आफ परसनल एक्सप्लेनेशन । मैने कभी यह नहीं

कहा कि देश के सारे अफसर कोई अमेरिका से या रूस से पैसा लेते हैं। मैंने यह कभी नहीं कहा। मैंने कहा कि कुछ लोग जरूर ऐसे हैं अफसरों में जिनका झुकाव अमेरिका की तरफ है या रूस की तरफ है। मैंने इतना ही कहा है। मैं इनसे प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ कर कि जो मैंने कहा है उस पर यह बोलें। पता नहीं मेरे मुंह में क्या-क्या यह डाल रहे हैं, धर्म डाल रहे हैं, मुसलमान डाल रहे हैं और बोले जा रहे हैं। मैं क्या करूं ? आप कृपा करके मेरी इनसे रक्षा कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूं।

श्री तुलशीदास जाधव : सभापति महोदय, अभी तक 40 वर्ष में मैंने कभी किसी के मुंह में कोई चीज नहीं डाली। उधर से बुरी बात उन्होंने कही तो वह बुरी है इतना ही मैंने कहा है। और कुछ नहीं। राष्ट्रीय संघ ने कहा, मुझे पता नहीं यह उसमें हैं या नहीं, उनका एक और स्लोगन है कि भारतीय-करण होना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि इन लोगों को छोड़ कर बाकी सब अभारतीय है क्या ? यह किसी को इस तरह से कुछ कहना कहां तक उचित है ? मैं आपसे कहता हूं जितने भारतीय अच्छे वर्कर यहां कांग्रेस में हों या और दूसरी पार्टी में हों, वह जितने अच्छे कार्यकर्त्ता हैं उतने तुलना की दृष्टि से इनके कार्यकर्त्ता हैं या नहीं, यह इनको देखना चाहिए अपने घर का मामला, दूसरे से कहने का कोई मतलब नहीं है। भारतीयकरण करो, किसी अफसर को नेशनलाइज करो, यह करो, वह करो, यह ठीक है अपने दिल की बात बाहर आप कहिए लेकिन इस तरह से पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहना कि यह अभारतीय हैं, यह दूसरे देश से पैसा लेते हैं, यह बातें कहना एक अच्छी राजकीय पार्टी के मेम्बर को शोभा नहीं देतीं। एक राजकीय पार्टी कहलाने वाले जैसे उनके लीडर जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी, संसद के अन्दर ऐसी अच्छी हिन्दी भाषा बोलने वाले, ऐसी पार्टी के अन्दर ऐसे लोग... (व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : अच्छी पार्टी आपने कैसे कहा ?

श्री तुलशीदास जाधव : इन्सानियत की दृष्टि से अच्छी कहा है विचार की दृष्टि से नहीं। विचार तो उन के बिलकुल खराब हैं जिन को कि देश में बिलकुल नहीं चलने देना चाहिए।

तो मैं यह कह रहा था कि इस तरह के बिचारें यहां रखना उचित नहीं है। इस रीति से दुनिया में जो विचार नए नये फैलते हैं उन को रोकना और हमारा जो विचार और संस्कृति है, केवल वही यहां रहे, तो आदान-प्रदान का जो तरीका है वह बन्द हो जायगा और एक स्टैग्नेंट वाटर की सी व्यवस्था पैदा हो जायगी जैसे पहले जमाने में लोग रहते थे कि अपना अपना काम करना, इस को ऊंचा, उस को नीचा मानना, इस तरह की समाज की रचना वह चाहे कितना भी रात और दिन कुछ भी कहें लेकिन यह हिन्दुस्तान कभी भी इस को सहन नहीं करेगा। सब धर्म के लोगों को साथ लेना यह इस हिन्दुस्तान की परम्परा रही है। जैसे कुरान शरीफ में कहा है कि मुहम्मद साहब के समय में जब क्रिस्चियन लोग अल्प संख्या में वहां पर थे तो उन्होंने कहा कि मेरे राज्य में, मदीना में या जहां भी उन का राज्य था, उसे में उन्होने कहा कि उन को मैं पहले संभालूंगा। इस रीति से इस देश में जो अल्प संख्या में हैं चाहे भाषा की दृष्टि से चाहे धर्म की दृष्टि से वह सब हमारे भाई हैं। उन को पहले संभालना होगा, और उन को साथ ले कर चलना होगा तब देश का उद्धार होगा।

सभापति महोदय : इस बिल के उपर दो घंटे का समय था। डेढ़ घंटा इस में लगा और अभी बहुत से लोग जो अपना बिल मूव करने

[सभापति महोदय]

वाले थे उनको उस वक्त मौका नहीं मिल सका, वह लोग उस वक्त मौजूद नहीं थे, इस लिए अब में इस डिस्कशन को बन्द करता हूँ और उन को पुकारता हूँ जिन्होंने अपने बिल दिए हैं।

17.27 hrs.

MOTHER'S LINEAGE BILL*

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि माता के पक्ष की ओर से वंशावली खोजने के अधिकार की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि माता के पक्ष की ओर से वंशावलि खोजने के अधिकार की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय।

The motion was adopted

श्री मधु लिमये : मैं विधेयक पेश करता हूँ।

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Substitution of article 168 and omissin of article 169 etc.)

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत में संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय।

The motion was adopted

श्री भोगेन्द्र झा : मैं विधेयक पेश करता हूँ।

JUDGES PROHIBITION ON HEARING IN CERTAIN CASES BILL*

SHRI A. S. SAIGAL (Bilaspur) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to regulate the procedure for prohibiting Judges of the Supreme Court or of a High Court from hearing and deciding the matter in which they are biased.

MR. CHAIRMAN : The question is :

> "That leave be granted to introduce a Bill to regulate the procedure for prohibiting Judges of the Supreme Court or of a High Court from hearing and deciding the matter in which they are biased."

The motion was adopted

SHRI A. S. SAIGAL : Sir, I introduced the Bill.

17.29 hrs.

HALF AN HOUR DISCUSSION

Impact of Increase in Fourth Five-Year Plan

SHRI S. S. KOTHARI (Mandsaur) : Sir, the decision to increase the public sector outlay by Rs. 1473 crores has been taken under political compulsion. The reduction of Rs. 1016 crores in private sector outlay would appear to be a sop to the redicals in the party who were pressing for such a reduction. The Important point is this. We can have a larger Fourth Five-Year Plan. But then the matching resources have to be found. The Government is unable to spelt out from where those resources emanate, where they are to come from, would I think, this amounts, to an exercise in planned fiscal recklessness.

It appears that the Planning Commission has learnt nothing and forgotton nothing from the their experience of the Third-Plan, The outlays had been increased considerably and the country experienced considerable inflation. Inflation is the most insidious form of taxation. It adversely

*Published in Gazette of India Extraordnary, Part II, Section 2, dated 27.2.70.